1993-94

2D Survey in Sanand-Jhalora, Palej-Bharuch, Jambusar-Davala, Hansot-Sajod, Padra-Jambusar, Amod-Gandhar, Balol east, Mehsana Horst, Bharuch-Jambusar, Ankaleshwar-Kosamba, North of Unawa-East of Patan, Surat-Olpad, Hansot-Rusamba, Borsad-Ankalav, Mahuda-Gamij, West of Patan, Puna-Mindhola and Gamij-Dehgam.

3D seismic survey in Kim-Wagwan Limbodra, Ankleshwar and Pansar Paliyad.

1994-95

2D seismic survey in Mehsana horst, Bharuch-jambusar, Ankaleshwar-kosamba, North of Unawa-East of Patan, Surat-olpad, Hansot-Kosamba, Borsad-Anklav, South of Padra, Harij-Khambel-becharaji, Gamij, Linch-nandasan, North Balol-Lanwa-Modhera, Puna-Mindhola, South east of Gandhi Nagar, South of Gamij.

3D seismic survey in Ankleshwar, Pansar-Paliyad, Gandhar Goladra.

1995-96

2 D seismic survey in South of Padra, Harij-Khambel-Bechraji, Gamij, Linch-Nandasan, South of Gamij, North Balol-Lanwa-Modhra, South east of Gandhi nagar, Nawagam-Bareja, Southern plunge of mehsana Host Asjol, Jotana-sobhasan, Linck-Nandasan-Baliasal, Mehsana road and west of Limbodra.

3 D seismic survey in Pansar-Paliyad and Gandhar-Goladra.

(c) and (d) Yes, Sir. The seismic data aquired during 1993-94 and 1994-95 have been proccessed and analysed. During last three years oil was discovered in two of new prospects viz. Halisa and Kambai identified on the basis of seismic surveys.

गरीबों के लिए मकान

669. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से सभी शहरी और ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कहा है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना के न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार कब तक यह योजना बनायेगी और सभी शहरी और ग्रामीण गरीबों को कब तक मकान मिल जायेंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं० 12992/96 (अहमदाबाद नगर निगम बनाम नवाब खां व गुलाम खां व अन्य) पर हाल ही के फैसले में यह अभिमत व्यक्त किया है कि सांविधिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से गरीबों और समाज के अकिंचन कमजोर वर्गों को आश्रय का अधिकार सुलभ करना राज्य का कर्तव्य होगा।

(ख) समुचित जन स्तर के अधिकार के घटक के रूप में पर्याप्त आवास के अधिकार की कार्मिक अधिप्राप्ति अनेक ठोस उपायों के जरिये, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय आवास नीति में है, के प्रति सरकार वचनबद्ध है।

(ग) चूंकि आवास निर्माण राज्य का विषय है। अतः इस बाबत खाद्य स्कमें राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना प्राथमिकताओं और धन स्रोतों के अनुसार तैयार की जाती हैं। केन्द्र सरकार भी इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, शहरी गरीबों के लिए आश्रय सुधार योजना, प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शहरी फुटपाथियों के लिए रैन बसेरा तथा सफाई सुविधायें बीड़ी कामगारों, कपड़ा मजदूरों मच्छुआरों आदि के लिए आवास स्कीमें चला रही हैं। इन सभी स्कीमों का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी गरीबों को आवास सुविधायें सुलाभ कराना है।

Annual Plan Allocation for Gujarat

670. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the annual plan allocation for 1996-97 demanded by the Gujarat Government and that granted by the Central Government; and